

महाप्रबंधक के नए-नए कारनामे के बाद भी प्रशासन व जनप्रतिनिधि मौन

विपक्ष की क्या है मजबूरी

अब सेवा सहकारी समिति कातलबोड़ी में नियमों की अनदेखी, प्रबंधक पर परिजनों को लाभ पहुंचाने का मामला

सिवनी नवभारत । जैसा कि नवभारत समाचार पत्र लगातार जिला सहकारी बैंक में हुई भ्रष्टाचार से संबंधित और भी अन्य मामलों को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों सहित विपक्ष को ध्यान आकर्षित करते हुए निष्पक्षता से खबर प्रकाशित कर रहा है इसके बाद भी विपक्ष की क्या मजबूरी है कि अभी तक इस गंभीर मामले में खामोश नजर आ रहा है वहीं केंद्र और राज्य सरकार में भाजपा की सरकार है और वर्तमान में सिवनी जिला में भी दो विधायक भाजपा के हैं और दो सांसद होने के बाद भी अभी तक इस मामले में इनका खामोश रहना भी कहीं ना कहीं महाप्रबंधक केके सोनी की राजनीति पकड़ से प्रशासन भी अब कार्रवाई करने से डर रहा है जिसका उदाहरण एक बार फिर एक नहीं दो दो मामले भी सामने आए हैं जहां एक ओर सिवनी जिले की सेवा सहकारी समिति कातलबोड़ी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। समिति के प्रबंधक सुरेश सनोडिया पर अपने ही परिवार के सदस्यों को समिति में रखने के आरोप लग रहे हैं, जिससे क्षेत्र में सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीणों और सहमित से जुड़े लोगों के बीच यह मामला जनचर्चा का विषय बना हुआ है।



और जानकारी के अनुसार प्रबंधक सुरेश सनोडिया ने अपने बेटे अभिषेक सनोडिया को समिति में कार्यरत रखा है। वहीं आरोप यह भी है कि उनके भतीजे राहुल सनोडिया को भी समिति में जिम्मेदारी दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नियुक्तियां नियमों के विपरीत हैं और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती हैं। जो इस समय पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि समिति में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह प्रबंधक के इशारों पर चल रही है। लोगों का आरोप है कि प्रशासक की भूमिका केवल औपचारिक होकर रह गई है और समिति में वही निर्णय लागू होते हैं जो प्रबंधक द्वारा तय किए जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सहकारी समितियों में पारिवारिक प्रभाव और मनमानी इसी तरह जारी रही तो आम किसानों का



भरोसा व्यवस्था से उठ सकता है। किसानों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि समिति में नियुक्तियां किन नियमों के तहत की गईं। इस मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक के.के. सोनी की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि उच्च स्तर से संरक्षण मिलने के कारण ही समिति में लंबे समय से मनमानी चल रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इधर गेहूं खरीदी केंद्रों में बड़ा खेल!

पोर्टल में हजारों किंटल दर्ज, लेकिन

जमीन पर नहीं दिख रहा गेहूं?

जिले के विभिन्न गेहूं खरीदी केंद्रों में खरीदी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पोर्टल में दर्ज गेहूं की मात्रा और केंद्रों में

वास्तविक रूप से उपलब्ध गेहूं के बीच भारी अंतर सामने आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरोप है कि पोर्टल में जितना गेहूं चढ़ाया गया है, उतना गेहूं कई खरीदी केंद्रों में जमीन पर मौजूद नहीं है।और सू्यों के अनुसार व्यापारी और कुछ जिम्मेदार कर्मचारियों की मिलीभगत से पोर्टल में अतिरिक्त गेहूं दर्ज किए जाने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि घाट और लेन-देन के खेल के चलते वास्तविक मात्रा से अधिक गेहूं ऑनलाइन दर्ज किया गया, जिससे शासन को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक के.के. सोनी आखिर मौके पर पहुंचकर जांच करने से क्यों बच रहे हैं। जिसमें अधिकारियों की निष्क्रियता से पूरे

नवभारत

सहकारिता कार्यवाई समिति के कर्मचारियों को थमाया सेवा मुक्ति आदेश

वही नए-नए कारनामे के बाद बरघाट विकास खंड के अन्तर्गत आने वाली सहकारी समिति लालपुर में एक बड़ी कार्यवाई सामने आई है जिसमे सहकारी समिति के पूर्व समिति प्रबंधक एवं एक अन्य कर्मचारी को प्रशासक के द्वारा सेवा मुक्ति आदेश थमाया गया है जिससे सहकारी समितियों में हड़कप की स्थिति निर्मित हो गई है और इस कार्यवाई को जिले की सबसे बड़ी कार्यवाई के रूप मे देखा जा रहा है तथा जिन्हें यह सेवा मुक्त आदेश थमाया गया है यह दोनो कर्मचारी पूर्व से ही निर्लबित थे और इसके बाद भी फिर क्यों थमाया सेवा मुक्त आदेश प्राप्त जानकारी के अनुसार सहकारी समिति लालपुर में उपायुक्त सहकारिता के आदेश पर गठित जांच दल के द्वारा धान उपार्जन से सम्बंधित पहलुओ पर जांच की गई थी और जांच प्रति वेदन उपायुक्त सहकारिता सिवनी को सौपा गया था एवं जांच प्रति वेदन के आधार पर संयुक्त रूप से दोनो कर्मचारियों पर 5559401 पवपन लाख उसंट हजार वार सी एक रुपये की वसुली कार्यवाई प्रस्तावित की गई थी और यह वसुली धान उपार्जन कार्य के लिये समिति को प्राप्त खाली बारदानो से जुड़ी हुई है जिसमे समिति को प्राप्त नये एवं पुराने बारदानो की वसुली के अलग अलग उल्लेख किया गया है सेवा मुक्त आदेश मे वर्णित के आधार पर पूर्व समिति प्रबंधक पर बारदानो की कुल वसुली राशि जांच प्रतिवेदन के आधार पर 3238218 बत्तीस लाख अउत्तीस हजार दो सौ अठारह रुपये निर्धारित की गई थी जिसमे से 255559 दो लाख पवपन हजार पांच सी



उसंट रुपये की राशि वेतन से वसूल करने के उपरांत शेष राशि 2982659 उन्तीस हजार बयासी हजार आठ सौ उसंट रुपये वसुली निर्धारित की गई थी तथा समिति के ही अन्य कर्मचारी पर 2321183 तथा 29 गटान नये बारदाने की वसुली राशि 1319500 एवं 10 गटान पुराने बारदाने की राशि 45500 सहित कुल राशि 4095683 चालीस लाख पंचानबे छे सौ तिरासी रुपये सिमटने वाली है अथवा अन्य कार्यवाई समिति की गई थी और कुछ राशि वेतन से भी वसुली करने के उपरांत 3694055 की वसुली की कार्यवाई प्रस्तावित थी संयुक्त पंजीयक जबलपुर के मौखिक निर्देश एवं बैठक कार्यवाई दिनांक 20/04/2026 के अनुसार दोनो कर्मचारियो के द्वारा की गई अनियमितता तथा वसुली की राशि जमा न करने के कारण प्रशासक के द्वारा 20 म ई 2026 को दोनो सहकारी समिति के कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है साथ ही वसुली की राशि जमा न करने पर वैधानिक कानूनी कार्रवाई एवं भू राजस्व की भांति चल

अवल सम्पति या अन्य माध्यमो से वसुली की प्रक्रिया अपनाने जाने का भी फरमान जारी किया गया है वैसे प्रशासक की जिले मे यह कार्रवाई जरूर समितियो मे हडकप पैदा कर रही किन्तु यह प्रश्न भी उठने लगे है की बारदानो की वसुली मे जब इनके द्वारा इतना बडा कदम उठाते हुऐ कर्मचारियो को सेवा मुक्त का फरमान जारी कर दिया गया वही बरघाट विकास खंड मे अनेको समितियो की जांच लम्बित है तथा धान के शार्टेज और वसुली के मामले मे अनेको समितिया ब्लेक लिस्टेड हो चुकी है धान शार्टेज जैसे मामले मे समितियो को लाखो की छति हुई है तथा धान खरीदी से प्राप्त होने वाली कमीशर मे प्रशासक डी के डेहरिया का यह कदम सहकारिता के लिये नया आगाज है अथवा यह कार्यवाई कागजो तक सिमटने वाली है अथवा अन्य कार्यवाई समिति की गई थी और शार्टेज की राशि लाखो मे है वसुली और कार्यवाई इसी तरह अनवरत जारी रहेगी यह तो आने वाला समय ही निरधारित करेगा समिति की जांच उपायुक्त सहकारिता कार्यालय के साथ साथ महा प्रबंधक के निर्देश पर बैंक शाखा धारनाकला के द्वारा भी की गई थी किन्तु उपायुक्त कार्यालय के जांच प्रतिवेदन पर यह कार्यवाई सामने आई है किन्तु महा प्रबंधक के निर्देश पर हुई जांच के आधार पर अब तक कार्यवाई क्यों नही हुई यह बात भी समझ से परे है।

मामले पर संदेह और गहरा गया है। किसानों और आम नागरिकों का कहना है कि यदि खरीदी केंद्रों में पोर्टल के अनुसार गेहूं उपलब्ध नहीं है तो यह सीधे तौर पर बड़ी जिसके कारण भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। दिखाई दे रहा है और खरीदी केंद्रों में कई स्थानों पर स्टॉक रजिस्टर और

वास्तविक भंडारण में भी अंतर बताए जाने की चर्चा है। इसके बावजूद अब तक किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं होना विभागीय कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है। किसानों का आरोप है कि छोटे किसानों के नाम पर खरीदी दिखाकर व्यापारियों को लाभ पहुंचाया गया और पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी आंखें

मूंदे बैठे हैं। और किसान परेशान हो रहे हैं जिससे किसानों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है जिले में यह भी चर्चा है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पोर्टल में दर्ज मात्रा और वास्तविक स्टॉक का बड़ा अंतर सामने आ सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन और शासन स्तर से उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है।

किसान ने मांग की है कि खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और राशियों सहित संबंधित व्यापारियों की मिली भगत से पोर्टल में दर्ज गेहूं की मात्रा पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

झांसा देकर हड़प ली जमीन, पीड़ित ने लगाई सुनवाई में गुहार

सिवनी नवभारत । मंगलवार को एक शख्स ने कलेक्टर से मिलकर गुहार लगाई कि उसकी जमीन पर किसी ने छल पूर्वक कब्जा कर लिया है। जिसे मुक्त कराया जाए। प्रभारी कलेक्टर ने इस मामले में अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।



दौरान उसकी मुलाकात पुलिस विभाग में कार्यरत देवेंद्र कुमार उपाध्याय से हुई। परिचय बहने पर उसका आना जाना घूरवाड़ा होने लगा। उपाध्याय ने उसकी जमीन देखी और लालच दिया कि इस स्थान पर पोल्ट्री फार्म खोलना फायदे का सौदा रहेगा। जिसके लिए 20 लाख रुपए का लोन मिल

सकेगा। इसके लिए शुरुआत में चार लाख रुपए जमा करने होंगे। शिवकुमार उसकी बातों में आ गया और उसने अपने खाते से उपाध्याय के खाते में एक लाख 85 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जमीन मोडगेज कराने की बात कह उपाध्याय उसे रजिस्ट्रार आफिस ले

देता रहा गोलमोल जवाब

आरोप है कि इसके बाद देवेंद्र उपाध्याय पोल्ट्री फार्म खोलने को लेकर गोलमोल जवाब देता रहा। ऐसा करते करते पांच साल निकल गए। जब शिवकुमार ने अपने पैसे वापस मांगे तो देवेंद्र ने उसे खत में न जाने की चेतावनी दी। जब शिवकुमार ने पटवारी से पता किया तो उसके पैसों तले जमीन खिसक गई। उपाध्याय ने 2021 में ही जमीन अपने नाम करा ली थी। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को भी आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब शिवकुमार अपने पैसों और जमीन को वापस पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। कलेक्टर ने इस मामले में अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कृषि विभाग के एक फैसले से 15–20 गांवों के किसान परेशान, कोहका स्थित कृषि केंद्र 15 दिनों से बंद

सरकारी केंद्रों में सर्वर डाउन, घंटो इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही खाद

सिवनी नवभारत । कोहका – पीपरडहोी सहित आसपास के 15 से 20 गांवों के सैकड़ों किसान इन दिनों खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग के एक फैसले के कारण कोहका स्थित पंजीकृत निजी कृषि केंद्र पिछले लगभग 15 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार कोहका गांव में शासन से पंजीकृत आदर्श ऑर्गेनिक कृषि केंद्र संचालित होता है, जहां से आसपास के किसान आसानी से

खाद एवं कृषि सामग्री प्राप्त कर लेते थे। लेकिन कृषि विभाग द्वारा केंद्र को सील किए जाने के बाद अब किसानों को खाद के लिए सिवनी एवं अन्य सरकारी केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक दिन कृषि केंद्र संचालक किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए थे। संचालक द्वारा पंजीकृत किसानों को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि आवश्यक कार्य के कारण दुकान उस दिन बंद रहेगी। इसी दौरान किसी किसान द्वारा कृषि विभाग कार्यालय में फोन कर दुकान बंद होने की सूचना दे दी गई।

इसके बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंची और बंद दुकान को बिना किसी पूर्व नोटिस के सील

कर चली गई। कृषि केंद्र संचालक ने बाद में विभाग से कई बार केंद्र का ताला खोलने का निवेदन किया और आवश्यक कार्य से बाहर जाने की बात स्वीकार करते हुए अपनी गलती भी मानी, लेकिन इसके बावजूद अब तक केंद्र नहीं खोला गया। किसानों का कहना है कि पहले जहां गांव के पास ही आसानी से खाद मिल जाती थी, अब उन्हें खाद लेने के लिए सिवनी या अन्य केंद्रों में पूरा दिन खराब करना पड़ा रहा है। ग्राम निवासी किसान आशा दुबे ने बताया कि कृषि केंद्र बंद होने के कारण उन्हें खाद के लिए सिवनी स्थित वेयरहाउस में पंजीयन कराना पड़ा। वहां सुबह से पहुंचने के बाद



शाम 5 बजे तक नंबर का इंतजार करना पड़ा, लेकिन समय समाप्त होने के कारण खाद नहीं मिल सकी।

इसके बाद दोबारा पंजीयन कर अगले दिन फिर लाइन में लगना पड़ा, लेकिन उस दिन भी सर्वर डाउन होने के कारण सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद जवाब मिला कि अब 24 तरीख के बाद

आकर खाद के संबंध में जानकारी लेना। किसानों का कहना है कि इस प्रकार उन्हें दो-दो और तीन-तीन दिन तक सरकारी केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इसके बावजूद खाद नहीं मिल पा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकारी केंद्रों में सर्वर डाउन, लंबी लाइन और अन्य व्यवस्थागत समस्याओं के कारण किसान पहले से परेशान हैं, तब निजी कृषि केंद्र को लंबे समय तक बंद रखना समझ से परे है।

लोगों का सवाल है कि क्या कृषि विभाग किसानों की समस्या हल करने के बजाय केवल कार्रवाई दिखाने में लगा हुआ है?

किसानों का कहना है कि विभाग को निजी केंद्रों को बंद करने की बजाय ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके।

क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि विभाग यदि इतनी ही सक्रियता किसानों को राहत देने, सर्वर व्यवस्था सुधारने और समय पर खाद उपलब्ध कराने में दिखाए तो किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

किसानों ने मांग की है कि जल्द से जल्द बंद पड़े कोहका स्थित कृषि केंद्र को पुनः शुरू कराया जाए ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके और उन्हें खाद के लिए भटकना न पड़े।

विरोध

पीजी कॉलेज में पकड़ाया फर्जी परीक्षार्थी, सिवनी की सड़कों पर सिवनी कांग्रेस कमेटी, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस करेगी आंदोलन

शिक्षा घोटाले के खिलाफ छात्र आंदोलन होगा तेज़, 15 दिन का अल्टीमेटम

सिवनी नवभारत । जो लोग इस मुगालते में हैं कि मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार करवाकर, झूठे मामले कायम कर हमारी आवाज़ को दबा देंगे, उन्हें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनकी इन गौदड़ भभकियों से न हम डरे हैं और न डरेंगे। बल्कि अब छात्रों के भविष्य और अधिकारों की यह लड़ाई पहले से भी अधिक तेज़ और व्यापक रूप से लड़ी जाएगी।

आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इस चरम पर पहुंच चुका है कि अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब और मेहनती छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री कॉलेज सिवनी में सामने आया कथित मुझ भाई फर्जीबाड़ है, जिसने पूरे शिक्षा तंत्र को समसा कर दिया है। सरकार के दबाव में कॉलेज



प्राचार्य ने महाविद्यालय की गरिमा और अस्मिता को तार-तार करने का कार्य किया है। इस पूरे फर्जीबाड़े में केवल छात्र ही नहीं, बल्कि कॉलेज प्राचार्य, परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारी और सत्ता से जुड़े सिवनी में सामने आया कथित मुझ भाई फर्जीबाड़ है, जिसने पूरे शिक्षा तंत्र को समसा कर दिया है। सरकार के दबाव में कॉलेज

रहूंगा।

एनएसयूआई अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि वे अपने कांग्रेस परिवार के उन सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे थाने में रहने के दौरान बाहर लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखा। विशेष रूप से जिला अध्यक्ष नरेश मरावी, मोहन सिंह चंदेल , राजा बघेल , तनवीर अहमद , हनीफ़ खान, सुरेंद्र करोशिया ,रंजित यादव, यशपाल भलावी , राजिक अकील, राजा खान मुर्लीन , शिव सनोदिया , युवा प्रोफ़ेसर अध्यक्ष आदित्य मोटू भूरा , नितिन डेहरिया, अंशुल अवस्थी ,शक्ति जडेजा , विपिन यादव , श्रध्ध ठाकुर, अदतान खान,उवेश खान, आबिद हुसेन सहित उन सभी साथियों का धन्यवाद, जिनके नाम अनजाने में छूट गए है उन्हें भी हृदय की गहराई से धन्यवाद।

साथ ही सिवनी ज़िले एवं प्रदेश के उन सभी पत्रकार बंधुओं को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस तानाशाह भाजपा सरकार के दबाव में ना आकर निर्भीकतापूर्वक सच्चाई को अपने समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल में प्रमुखता से दिखाया। मैं इंजी.धनंजय सिंह आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि इस लड़ाई में मैं हमेशा प्रथम पंक्ति में खड़ा रहूंगा और छात्र हितों की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करता रहूंगा। यदि आगामी 15 दिनों के भीतर पुलिस प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती, तो बहुत जल्द सिवनी की सड़कों पर सिवनी कांग्रेस कमेटी, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के द्वारा फिर इंकलाब की गूँज सुनाई देगी।

गंगा दशहरा पर जलस्त्रोतों का पूजन कर निकाली कलश यात्रा

बरघाट नवभारत । मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन की चयनित नवांकुर संस्था मां शक्ति संस्थान पखारा सेक्टर क्रमांक-4 एवं ग्राम विकास विजय समिति पखारा, कोसमी, सरखकला, के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर जल स्रोतों का पूजन एवं गंगा कलश यात्रा 25 मई मौलवार समय 9:00 बजे से प्रारंभ किया गया है। जिला समन्वयक जी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद शिवनी के मार्गदर्शन में एवं ब्लॉक समन्वयक के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य जन सहभागिता से जल संरक्षण और संरक्षण कार्यों का क्रियान्वयन करना है। जल स्रोतों के

पुनर्जीवन एवं जीवनोंद्वार कर जल संरक्षण जल संवर्धन के लिए ग्राम की कम नदी में पूजा अर्चना कर सभी के द्वारा श्रमदान कर सभी को शपथ दिलाई गई है। ग्राम के मंदिर में जल चढ़ाया गया है। महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकली गई है। सभी के द्वारा नर लगवाया गया है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, पानी कौन बचाएगा हम बचाएंगे हम बचाएंगे, वृक्ष कौन लगाएगा हम लगाएंगे हम लगाएंगे, और सभी को जन सहभागिता के साथ सहयोग करने हेतु प्रेरित किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच , सचिव, रोजगार सहायक, कर्मचारी, ग्राम के पुरुष महिलाएं, ग्राम विकास प्रेस फुटन समिति के अध्यक्ष, सचिव, एवं सदस्य, छात्र छात्राएं एवं नवांकुर संस्था के कार्यक्रम समन्वयक तथा सदस्य लोगोकी सहभागिता रही।

खुसीपार वेयरहाउस में लगी आग, बड़ी दुर्घटना टली

छपारा । छपारा नगर के समीप ग्राम खुसीपार स्थित बैनगंगा विपणन सहकारी समिति के वेयरहाउस में बुधवार 28 मई को दोपहर करीब डेढ़ बजे अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वेयरहाउस के पास रहने वाले कुछ युवकों ने समय रहते धुआं और आग को लपेटे दिखां तथा तत्काल सहकारी समिति के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही छपारा थाना पुलिस एवं नगर परिषद छपारा को फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। फायर वाहन चालक रविंद्र पटेल और फायरफाइटर्स ने तत्परता दिखाते हुए करीब एक घंटे की कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनों की इस घटना में लगभग एक दर्जन से अधिक बारदाने के बंडल जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना पर छपारा थाना का 112 वाहन भी मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। भीषण गर्मी के बीच, जहां तापमान 43 डिग्री सेंटीसेस तक पहुंच रहा है, स्थानीय लोगों की सतर्कता और प्रयासन को त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। फिलहाल पुलिस एवं संबंधित विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं।